आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
सोमवार 10.03.2025
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शिक्षा नीति और परिसीमन के मुद्दों पर हंगामे के साथ शुरू हुआ।
- आवास विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में नये शहरों की स्थापना के लिए कार्य शुरू किया।
- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य की समृद्ध पाक परंपराओं और फूड टूरिज्म को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर बल दिया।
- प्रदेश के सरकारी अधिकारियों को ''क्वालिटी कनेक्ट ऐप'' के जरिए, भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों से जागरूक किया जाएगा।

बजट सत्र

बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन आज संसद के दोनों सदनों में शोर–शराबा हुआ। तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल को लेकर लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर डीएमके और कांग्रेस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद टी. सुमति ने तमिलनाडु को धन आवंटित करने का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए श्री प्रधान ने आरोप लगाया कि डीएमके ने पीएम श्री योजना तमिलनाडु में लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में वह इससे मुकर गई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके, तमिलनाडु के विद्यार्थियों के प्रति वचनबद्ध नहीं है और वह उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।

वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वर्ष 2024–25 के लिए दूसरे चरण की अनुपूरक अनुदान मांग पेश की। उन्होंने सदन में वर्ष 2025–26 के लिए मणिपुर से संबंधित बजट भी पेश किया।

नए शहर स्थापना कार्य

आवास विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में नये शहरों की स्थापना के लिए कार्य शुरू कर दिया है। ये जानकारी देते हुए आवास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विभाग के निर्देशन में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा नये शहरों की स्थापना के लिए विस्तृत अध्ययन के बाद यह कार्य शुरू किया गया है। आवास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सबसे पहले पौड़ी जिले के बेलकेदार, श्रीनगर के तहत स्थल चयन करते हुए प्रस्तावित शहर के अन्तर्गत आने वाली सरकारी भूमि, आवास विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही के साथ ही इस महायोजना के लिए कन्सल्टेन्ट चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। इसके लिए उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को इस माह के अंत तक कन्सल्टेन्ट के चयन की प्रक्रिया पूरी करने और आगामी 06 माह में प्रस्तावित शहर की महायोजना और मॉडल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी शीघ्र ही नये शहर की स्थापना के लिए भूमि चयन की कार्यवाही पूरी करने के लिये भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार के अवसरों के साथ आवासीय सुविधाओं के साथ नये शहरों की स्थापना पर कार्य करना विभाग की प्राथमिकता है। आवास मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण यातायात और अन्य अवस्थापना सुविधाओं पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है, जिस कारण नये शहरों की ओर कदम बढ़ाना समय की आवश्यकता है।

छापेमारी अभियान

प्रदेशभर में होली के त्योहार के मद्देनजर मिलावटी खाद्य पदार्थों की संभावना को देखते हुए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, चम्पावत जिले के मैदानी इलाकों टनकपुर और बनबसा के साथ ही चम्पावत, पाटी और खेतीखान के शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार के नेतृत्व में रेस्ट्रोरेंट, मिठाई व किरानों की दुकानों में वृहद रूप से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दुकानों में एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ को हटाने और मिठाइयों की सैंपलिंग ली जा रही है। साथ ही स्वच्छता न रखने पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। चम्पावत के प्रभारी जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने बताया कि इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए जगह–जगह छापा मार अभियान चलाया जा रहा है।

राज्यपाल

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य की समृद्ध पाक परंपराओं और फूड टूरिज्म को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड अपनी विशिष्ट खाद्य संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो गढ़वाल और कुमाऊँ की पारंपरिक विरासत से जुड़ी हुई है। राज्यपाल से आज राजभवन में भारतीय पाककला महासंघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान महासंघ के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को भारतीय पाककला को वैश्विक स्तर तक पहुँचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। राज्यपाल ने महासंघ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन और श्री अन्न न केवल पौष्टिक हैं, बल्कि इनमें विशिष्ट सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्यवर्धक गुण भी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन पारंपरिक व्यंजनों को देश–विदेश में लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने श्री अन्न जैसे– मंडुआ, भट्ट आदि के साथ ही पिस्यूं लूण जैसे स्थानीय खाद्य तत्वों को उत्तराखण्ड की प्राचीन खान–पान परंपराओं का प्रतीक बताते हुए कहा कि इन पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की आवश्यकता है।

भारतीय मानक ब्यूरो

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो, देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी की ओर से सभी विभागों को भेजी गई होली की शुभकामनाओं के साथ "क्वालिटी कनेक्ट" अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों को "क्वालिटी कनेक्ट" ऐप के माध्यम से गुणवत्ता मानकों के प्रति संवेदनशील बनाना है। आज देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल से मुलाकात के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद चार अलग–अलग टीमों द्वारा विभिन्न विभागों में अधिकारियों को जागरूक करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस पहल के जरिए गुणवत्ता नियंत्रण, मानकों की अनिवार्यता और उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अभियान से सरकारी विभागों में गुणवत्ता जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा और मानकों के अनुरूप कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित होगी।

बालिकाओं का भ्रमण

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए पौड़ी जिले के सभी विकासखण्डों से दो–दो बालिकाओं का चयन कर कुल 30 बालिकाओं को एक्सपोजर विजिट के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, नरेंद्र नगर भेजा गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र थपलियाल ने बताया कि इस विजिट से बालिकाओं में न केवल आत्मरक्षा की क्षमता विकसित होगी, बल्कि वे अपने अधिकारों को भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगी।
वहीं, एक्सपोजर विजिट को लेकर बालिकाएं काफी उत्साहित दिखीं।

जन संवाद

रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 26 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 11 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष समस्याओं को, समाधान के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि जन संवाद कार्यक्रम में सड़क, बिजली, पानी और अतिक्रमण से जुड़ी कुछ शिकायतें सामने आईं, जिन पर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर समाधान के आदेश दिए गए।